









समीर वानखेड़े को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका

# आर्यन खान की वेबसीरीज पर दायर मानहानि याचिका खारिज

नई दिल्ली, 26 सितंबर (एजेंसियां)

ईआरएस अधिकारी और नारकेटिक्स कंट्रोल ब्लॉग (एनसीआर) के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। वानखेड़े ने अभिनेता शारुख खान और गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, ओटोटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स और अन्य के खिलाफ 2 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा करते हुए याचिका दाखिल की थी।

अदालत का कहना है कि यह याचिका यहां विचार योग्य नहीं है। हालांकि, कोर्ट ने उनको याचिका में संशोधन करने और उपयुक्त कार्रव में दोबारा दाखिल करने की छूट दी है।

यह मामला साल 2021 में चर्चित क्रूज इंस केस से जुड़ा है, जिसमें समीर वानखेड़े ने आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। आर्यन को इस मामले में 27 दिन तक जेल में रहना पड़ा था, लेकिन



बाद में उन्हें कलीन चिट मिल गई। आर्यन खान ने इसी अनुभव को आधार बनाकर वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' बनाई, जिसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया।

समीर वानखेड़े का आरोप है कि इस सीरीज में उन्हें नाम लिए बिना दियाया गया है और एक किरदार उनकी तरह

की यूनिफॉर्म, अंदाज और भूमिका निभाता है, जिससे उनकी व्यक्तिगत और पेशेवर छवि को नुकसान पहुंचा है। उनका कहना है कि यह वेब सीरीज दुभावनापूर्ण इरादे से बनाई गई है ताकि उन्होंने आरोप लगाया कि सीरीज में ड्रग विरोधी एजेंसियों को गलत तरीके

से पेश किया गया है, जिससे आप जनता का इन संस्थाओं पर विश्वास कमज़ोर होता है।

वानखेड़े ने अपनी याचिका में कोर्ट से अपील की थी कि इस सीरीज को प्रतिबंधित किया जाए और रेड चिलीज और नेटफ्लिक्स को 2 करोड़ रुपए हर्जाना देने का आदेश दिया जाए।

उन्होंने बताया कि यह रकम टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में कैमर मीरों की मदद के लिए दान में दी जाएगी।

वानखेड़े ने एक विशेष सीन पर भी आपत्ति जताई, जिसमें एक किरदार 'सत्यमेव यजते' का नारा लगाने के बाद गलत इशारा दिखाता है। उनका कहना है कि यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान है और इससे देश की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसके साथ ही उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय व्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के उल्घंघन की बात भी कही।

## श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग के हाल ही में बंद होने से कश्मीर के बागवानी क्षेत्र को 1500 करोड़ का नुकसान

जम्मू, 26 सितंबर (ब्लॉग)

जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले बागवानी क्षेत्र को श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग के बंद होने के कारण भारी नुकसान हुआ है।

वानखेड़े ने अपनी याचिका में कोर्ट से अपील की थी कि इस सीरीज को प्रतिबंधित किया जाए और रेड चिलीज और नेटफ्लिक्स को 2 करोड़ रुपए हर्जाना देने का आदेश दिया जाए।

उन्होंने बताया कि यह रकम टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में कैमर मीरों की मदद के लिए दान में दी जाएगी।

सोपोर स्थित एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फल मंडी के अध्यक्ष फैब्रिय अहमद मलिक उर्फ काका जी ने आरोप लगाया कि सरकार संकट के अनुसार गंभीरता से बचने के अध्यक्ष फैब्रिय अहमद मलिक उर्फ काका जी ने आरोप लगाया कि सरकार संकट के लिए तत्काल रक्षा सहायता मांग की चाहिए।

स्थिति की गंभीरता पर भी प्रकाश डालते हुए फैब्रिय अहमद मलिक ने खुलासा किया कि अकेले सोपोर फल मंडी को लगभग 600-700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि पूरे कश्मीर में कुल 1,500 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। क्योंकि जल्दी खराब होने वाले फलों की खेप कई दिनों तक



गंभीरता से लेना चाहिए और उत्पादकों को हर संभव मुआवजा प्रदान करना चाहिए। उन्होंने मांग की कि अधिकारियों को फल

उत्पादकों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (कर्सीसी) क्रण माफ करना चाहिए और साथ ही बागवानी उद्योग को बचाने के लिए केंद्र सरकार से एक विशेष राहत पैकेज की मांग करनी चाहिए। यह उल्लेखनीय है कि श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग, घाटी का देश के बाकी हिस्सों से एकमात्र बाहरमासी सड़क संपर्क, हाल के हफ्तों में लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण बार-बार बंद हुआ, जिससे सेब

करना चाहिए।

वाहनों की चाहिए।

## दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध में हीलाहवाली पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा-केंद्र बनाए ठोस नीति

नई दिल्ली, 26 सितंबर

(एजेंसियां)।



सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध के अपने आदेश को प्रभावी ढंग से लगान न करने पर नाराजी जताई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि सभी हितधारकों के साथ मिलकर प्रतिबंध लागू करने की एक ठोस नीति तैयार की जाए।

सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि सभी हितधारकों जैसे पटाखा निर्माताओं, राज्य सरकारों और पर्यावरण विशेषज्ञों के साथ मिलकर प्रतिबंध लागू करने की एक ठोस नीति तैयार की जाए।

इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री को लेकर दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों (पर्यावरण-अनुकूल पटाखों) के निर्माण को संशर्त अनुमति दे दी है। बैंच ने शर्त लगाई कि ये पटाखे दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों के लिए लागू होनी चाहिए।

सीजे आई ने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए बताया था, मैं पिछले साल संदिग्धों में अमृतसर गया था। वहां प्रदूषण की स्थिति दिल्ली से भी बदतर थी। अगर पटाखों पर प्रतिबंध लगाना है तो पूरे देश में लगना चाहिए।

दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन

था कि अगर दिल्ली-एनसीआर के लोगों को स्वच्छ हवा का अधिकार है, तो दूसरे शहरों के निवासियों को क्या नहीं?

उन्होंने जोर देकर कहा था कि प्रदूषण नियंत्रण की नियमों के लिए जांच के घेरे में एए स्वामी चैत्यनांद समस्वती की अधिम जमानत याचिका खारिज कर दी। यह आदेश पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि आरोपों की प्रकृति जांच के लिए इस चरण में हिरासत में पूछताछ की मांग करती है। यह धरना ऐसे समय में हुई है जब अदालत ने एक स्वयंभू धर्मगुरु के खिलाफ कथित धोखाधड़ी, जाली द्वारा लगाने के लिए बेईमानी से

पटाखों की बिक्री को लेकर दिल्ली-एनसीआर में तोड़वाई में अतिम फैसला लगाया गया। मामले में अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होनी चाहिए।

इससे पहले, 12 सितंबर को

सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण को लेकर कही की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण को लेकर कहा कि यह आदेश पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि आरोपों की प्रकृति जांच के लिए इस चरण में हिरासत में पूछताछ की मांग करती है। यह धरना ऐसे समय में हुई है जब अदालत ने एक स्वयंभू धर्मगुरु के खिलाफ कथित धोखाधड़ी, जाली द्वारा लगाने के लिए बेईमानी से

सुनवाई की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण को लेकर कहा कि यह आदेश पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि आरोपों की प्रकृति जांच के लिए इस चरण में हिरासत में पूछताछ की मांग करती है। यह धरना ऐसे समय में हुई है जब अद





संपादकीय

लद्धाख कितना 'जेन जी'

**लह** लद्धाख जैसे शांत और शीतल क्षेत्र में अचानक आगजनी, पतथरवाजी,

हिंसक माहौल देखें-सुन कर देख चौकन्ना हो गया होगा! लद्धाख 2250 मीटर से 7742

मीटर की ऊँचाई पर स्थित ऐसा क्षेत्र है, जहाँ रुहानियत और सुकून बसते हैं। यह

सीमावर्ती क्षेत्र भी है। वास्तविक निवारण रेखा (एलएसी) का आसपास भारत और चीन

के हिस्सों से समाझौता, कुछ समय पहले तक, तैनात हो एवं सेनानी की पीढ़ी हट

चुकी है, जोकि दोनों देशों की बीच समझौता-वातां के पैर जारी है। पहले तो युद्ध-सा

माहौल था। तरसु ये मिस तरह परवान-प्रदर्शन किए गए, उन्हें देख कर चीन की निगाहें

भी फैल गई होंगी! बेशक आपारण अनशन पर 15 दिन से बैठे सोनम वाग़वाह के निरोध-

प्रशंसन की तुलना अरब संरित और नेपाल के 'जेन जी' विद्रोह से की, लेकिन यह देश-

विरोधी बाबा है, क्योंकि युवा इससे और भी ज्यादा भड़क सकते हैं। सोनम ने अपना

अनशन भी वापस ले लिया और शांति की अपील भी की। यह कैसे दोगलाप है! लद्धाख

को केंद्रसामित क्षेत्र का दर्जा-मोरी सरकार ने

ही दिया था, अलवाह यह क्षेत्र दशकों से

जम्मू-कश्मीर की छाया तो अपने स्वतंत्र

अस्तित्व का विकास और विस्तार के लिए

तरस रहा था। 2019 के बाद अब जम्मू-

कश्मीर और लद्धाख दोनों ही केंद्रसामित क्षेत्र

हैं। अंदोलन हिंसक बयां हुआ, जिसमें 4-5

मीटों ही गई हैं और 70 से अधिक लोग घायल हो

गए? प्रश्नसन को कप्रूप लगाना पड़ा,

पहले तक, तैनात हो। अब सेनाएँ काफी

इंटरन की सप्लाई रोकनी पड़ी और 4 या

पीछे फूट चुकी हैं क्योंकि दोनों देशों द्वारा उससे भयने पर यांवंदी

समझौता-वातां के दोरा हो गया। इहले तो

अब योंगे और जलसे-

-विरोध-प्रशंसन किए गए, उन्हें देख कर

रीनी की निगाहें भी फैल गई होंगी। बेशक

आपारण अनशन पर 15 दिन से बैठे सोनम

वांगूक ने विरोध-प्रशंसन की तुलना अरब

संरित और नेपाल के 'जेन जी' विद्रोह से

की, लेकिन यह देश-विरोधी बयां है,

क्योंकि युवा इससे और भी ज्यादा भड़क

सकते हैं। सोनम ने अपना अनशन भी

वापस ले लिया और शांति की अपील भी

की। यह कैसे दोगलाप है। लद्धाख को

केंद्रसामित क्षेत्र का दर्जा-मोरी सरकार ने

ही दिया है। अलवाह यह देश-विरोधी

क्षेत्र है। अंदोलन हिंसक बयां हुआ।

जलसे-विरोध-प्रशंसन के लिए

तरस रहा था। 2019 के बाद अब जम्मू-

-कश्मीर और लद्धाख दोनों ही केंद्रसामित

क्षेत्र के लिए विकास और शांति की अपील भी

हो गई है। लद्धाख में जिस देश-विरोधी

क्षेत्र की निगाहें भी फैल गई होंगी। लद्धाख

में जम्मू-कश्मीर की छाया तो डूब जाएगी।

जलसे-विरोध-प्रशंसन के लिए लद्धाख को

केंद्रसामित क्षेत्र का दर्जा-मोरी सरकार ने

ही दिया है। अलवाह यह देश-विरोधी

क्षेत्र है। अंदोलन हिंसक बयां हुआ।

जलसे-विरोध-प्रशंसन के लिए लद्धाख को

केंद्रसामित क्षेत्र का दर्जा-मोरी सरकार ने

ही दिया है। लद्धाख में जिस देश-विरोधी

क्षेत्र की निगाहें भी फैल गई होंगी। लद्धाख

में जम्मू-कश्मीर की छाया तो डूब जाएगी।

जलसे-विरोध-प्रशंसन के लिए लद्धाख को

केंद्रसामित क्षेत्र का दर्जा-मोरी सरकार ने

ही दिया है। लद्धाख में जिस देश-विरोधी

क्षेत्र की निगाहें भी फैल गई होंगी। लद्धाख

में जम्मू-कश्मीर की छाया तो डूब जाएगी।

जलसे-विरोध-प्रशंसन के लिए लद्धाख को

केंद्रसामित क्षेत्र का दर्जा-मोरी सरकार ने

ही दिया है। लद्धाख में जिस देश-विरोधी

क्षेत्र की निगाहें भी फैल गई होंगी। लद्धाख

में जम्मू-कश्मीर की छाया तो डूब जाएगी।

जलसे-विरोध-प्रशंसन के लिए लद्धाख को

केंद्रसामित क्षेत्र का दर्जा-मोरी सरकार ने

ही दिया है। लद्धाख में जिस देश-विरोधी

क्षेत्र की निगाहें भी फैल गई होंगी। लद्धाख

में जम्मू-कश्मीर की छाया तो डूब जाएगी।

जलसे-विरोध-प्रशंसन के लिए लद्धाख को

केंद्रसामित क्षेत्र का दर्जा-मोरी सरकार ने

ही दिया है। लद्धाख में जिस देश-विरोधी

क्षेत्र की निगाहें भी फैल गई होंगी। लद्धाख

में जम्मू-कश्मीर की छाया तो डूब जाएगी।

जलसे-विरोध-प्रशंसन के लिए लद्धाख को

केंद्रसामित क्षेत्र का दर्जा-मोरी सरकार ने

ही दिया है। लद्धाख में जिस देश-विरोधी

क्षेत्र की निगाहें भी फैल गई होंगी। लद्धाख

में जम्मू-कश्मीर की छाया तो डूब जाएगी।

जलसे-विरोध-प्रशंसन के लिए लद्धाख को

केंद्रसामित क्षेत्र का दर्जा-मोरी सरकार ने

ही दिया है। लद्धाख में जिस देश-विरोधी

क्षेत्र की निगाहें भी फैल गई होंगी। लद्धाख

में जम्मू-कश्मीर की छाया तो डूब जाएगी।

जलसे-विरोध-प्रशंसन के लिए लद्धाख को

केंद्रसामित क्षेत्र का दर्जा-मोरी सरकार ने

ही दिया है। लद्धाख में जिस देश-विरोधी

क्षेत्र की निगाहें भी फैल गई होंगी। लद्धाख

में जम्मू-कश्मीर की छाया तो डूब जाएगी।

जलसे-विरोध-प्रशंसन के लिए लद्धाख को

केंद्रसामित क्षेत्र का दर्जा-मोरी सरकार ने

ही दिया है। लद्धाख में जिस देश-विरोधी

क्षेत्र की निगाहें भी फैल गई होंगी। लद्धाख

में जम्मू-कश्मीर की छाया तो डूब जाएगी।

जलसे-विरोध-प्रशंसन के लिए लद्धाख को

केंद्रसामित क्षेत्र का दर्जा-मोरी सरकार ने

ही दिया है। लद्धाख में जिस देश-विरोधी

क्षेत्र की निगाहें भी फैल गई होंगी। लद्धाख

में जम्मू-कश्मीर की छाया तो डूब जाएगी।

जलसे-विरोध-प्रशंसन के लिए लद्धाख को

केंद्रसामित क्षेत्र का दर्जा-मोरी सरकार



## बलुचिस्तान लिबरेशन फ्रंट का खारान में सुरक्षा बलों के केंद्रीय शिविर पर हमला, सोराब में हथियार और वाहन छीने

केटा (बलुचिस्तान) प्राक्षिप्तान, 26 सितंबर (एजेंसिया)।

बलुचिस्तान के खारान शहर के बीच-बीच स्थित पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के केंद्रीय शिविर पर बड़ा हमला हुआ है। हमले में हुए जान-माल की शक्ति की तकाल पुष्टि नहीं हो सकती। उसर, सोराब में अज्ञात बंदूकधारियों ने संघीय सरकार के सुरक्षा कर्मचारियों को बंधक बनाकर उनके हाथियार और वाहन छीन लिए। इस बीच, पूर्व बदाव छार नेता जुवैर बलोच को उनके तेक गाव मस्तुर में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। पाकिस्तान सुरक्षा बलों के छापे में उनकी मौत हो गई थी। खारान हमले और सोराब की घटना पर अभी तक कोई सरकारी बयान

सामने नहीं आया है।

रिपोर्ट के अनुसार खारान हमले की जिम्मेदारी बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (बीएलएफ) ने ली है। प्रंत के प्रवक्ता मेजर लाचरों ने आधिकारिक हथियारों और गेंडर बलोचों के साथ खारान शहर के केंद्र में कब्जे वाले पाकिस्तानी बलों के केंद्रीय शिविर पर हमला किया। प्रवक्ता ने दावा किया कि इसके बलोचिस्तान के गांवों, पहाड़ों, शहरों और राजमार्गों पर जबरिया कब्जा करने वाली पाकिस्तान की सेना को उत्ताकर ही दम लेगा।

सोराब की घटना की अभी तक किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली है। रिपोर्ट के अनुसार, सोराब तारिकी डैम इलाके में दजनों हथियारबद्द लोगों ने हमला कर लिया है। इसके बाद बलोच को सुर्दू-ए-खाक कर दी गया था। इसके बाद बलोच छात्र संगठन सहित विभिन्न प्रगतिशील जगीरीय दलों के नेता, नागरिक समाज के प्रतिनिधि, सरकारी उपकरण छीन कर अधिकारियों को बंधक बना लिया। इसके अलावा हथियारबद्द लोगों ने पास की लेही और सरद सामग्री लूट रहा है। बलोचिस्तान के राजमार्ग पर हमलाकर हथियार और रसद सामग्री लूट रहा है। बलोचिस्तान के जारी रहने के बाद, बलोचिस्तान में आवाजों को बलपूर्वक दबाने की कोशिश कर रहा है।

एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, दलवांदन क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना के हाथों भारे गए बलोच छात्र

### न्यूज ब्रीफ

**शहबाज-मुनीर की फिर इंटरनेशनल बेइज्जती ट्रंप से मिलने के लिए क्वाइट हाउस में करना पड़ा लंबा इंतजार**

वाशिंगटन, 26 सितंबर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फिल्ड मार्शल असीम मुनीर की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ओवल ऑफिस में मुलाकात के दौरान क्वाइट हाउस की असहजता देखने को मिला। मुलाकात से पहले दोनों नेताओं को करीब एक घंटे तक इंतजार करना पड़ा। इसी दौरान ट्रंप ने पत्रकरण से बातचीत में चुटकी लेते हुए कहा, \*पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फिल्ड मार्शल शायद इस कर्मर में मौजूद हों, क्योंकि वह देर से हैं।\* इस टिप्पणी को लेकर पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा।

23 सितंबर को भी हुई थी अनौपचारिक मुलाकात।

इससे पहले 23 सितंबर को शहबाज शरीफ की ट्रंप से एक अनौपचारिक मुलाकात हुई थी। यह ब्रिटिश ट्रंप और आठ इस्लामिक-अरब देशों के नेताओं के साथ हुई वार्ता के बाद आयोजित की गई थी।

उस समय पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री विदेश मंत्री इशाक डार भी मौजूद थे। क्वाइट हाउस के जानकारों का मानना है कि यह मुलाकात हाल के वर्षों में बिंगड़े रिश्तों के बाद अमेरिका और पाकिस्तान के बीच बढ़ी नजदीकियों का संकेत है।

अनेकों को पुरानी बीमारियों पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणाप्रति अस्वीकार करना है कि इसकी भाषा पर उसे अपत्ति है। संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक विदेशी इशाक डार भी मौजूद थे। क्वाइट हाउस के जानकारों का मानना है कि यह मुलाकात हाल के वर्षों में बिंगड़े रिश्तों के बाद अमेरिका और पाकिस्तान के बीच बढ़ी नजदीकियों का संकेत है।

अनेकों को पुरानी बीमारियों पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणाप्रति अस्वीकार करना है कि इसकी भाषा पर उसे अपत्ति है। संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक विदेशी इशाक डार भी मौजूद थे।

राष्ट्र के प्रतिनिधियों से बात करते हुए राष्ट्रपति एक निपटने और अस्वीकार करना है कि इसकी भाषा पर उसे अपत्ति है। संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक विदेशी इशाक डार भी मौजूद थे।

राष्ट्र के प्रतिनिधियों से बात करते हुए राष्ट्रपति एक निपटने और अस्वीकार करना है कि इसकी भाषा पर उसे अपत्ति है। संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक विदेशी इशाक डार भी मौजूद थे।

राष्ट्र के प्रतिनिधियों से बात करते हुए राष्ट्रपति एक निपटने और अस्वीकार करना है कि इसकी भाषा पर उसे अपत्ति है। संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक विदेशी इशाक डार भी मौजूद थे।

राष्ट्र के प्रतिनिधियों से बात करते हुए राष्ट्रपति एक निपटने और अस्वीकार करना है कि इसकी भाषा पर उसे अपत्ति है। संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक विदेशी इशाक डार भी मौजूद थे।

राष्ट्र के प्रतिनिधियों से बात करते हुए राष्ट्रपति एक निपटने और अस्वीकार करना है कि इसकी भाषा पर उसे अपत्ति है। संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक विदेशी इशाक डार भी मौजूद थे।

राष्ट्र के प्रतिनिधियों से बात करते हुए राष्ट्रपति एक निपटने और अस्वीकार करना है कि इसकी भाषा पर उसे अपत्ति है। संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक विदेशी इशाक डार भी मौजूद थे।

राष्ट्र के प्रतिनिधियों से बात करते हुए राष्ट्रपति एक निपटने और अस्वीकार करना है कि इसकी भाषा पर उसे अपत्ति है। संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक विदेशी इशाक डार भी मौजूद थे।

राष्ट्र के प्रतिनिधियों से बात करते हुए राष्ट्रपति एक निपटने और अस्वीकार करना है कि इसकी भाषा पर उसे अपत्ति है। संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक विदेशी इशाक डार भी मौजूद थे।

राष्ट्र के प्रतिनिधियों से बात करते हुए राष्ट्रपति एक निपटने और अस्वीकार करना है कि इसकी भाषा पर उसे अपत्ति है। संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक विदेशी इशाक डार भी मौजूद थे।

राष्ट्र के प्रतिनिधियों से बात करते हुए राष्ट्रपति एक निपटने और अस्वीकार करना है कि इसकी भाषा पर उसे अपत्ति है। संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक विदेशी इशाक डार भी मौजूद थे।

राष्ट्र के प्रतिनिधियों से बात करते हुए राष्ट्रपति एक निपटने और अस्वीकार करना है कि इसकी भाषा पर उसे अपत्ति है। संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक विदेशी इशाक डार भी मौजूद थे।

राष्ट्र के प्रतिनिधियों से बात करते हुए राष्ट्रपति एक निपटने और अस्वीकार करना है कि इसकी भाषा पर उसे अपत्ति है। संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक विदेशी इशाक डार भी मौजूद थे।

राष्ट्र के प्रतिनिधियों से बात करते हुए राष्ट्रपति एक निपटने और अस्वीकार करना है कि इसकी भाषा पर उसे अपत्ति है। संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक विदेशी इशाक डार भी मौजूद थे।

राष्ट्र के प्रतिनिधियों से बात करते हुए राष्ट्रपति एक निपटने और अस्वीकार करना है कि इसकी भाषा पर उसे अपत्ति है। संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक विदेशी इशाक डार भी मौजूद थे।

राष्ट्र के प्रतिनिधियों से बात करते हुए राष्ट्रपति एक निपटने और अस्वीकार करना है कि इसकी भाषा पर उसे अपत्ति है। संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक विदेशी इशाक डार भी मौजूद थे।

राष्ट्र के प्रतिनिधियों से बात करते हुए राष्ट्रपति एक निपटने और अस्वीकार करना है कि इसकी भाषा पर उसे अपत्ति है। संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक विदेशी इशाक डार भी मौजूद थे।

राष्ट्र के प्रतिनिधियों से बात करते हुए राष्ट्रपति एक निपटने और अस्वीकार करना है कि इसकी भाषा पर उसे अपत्ति है। संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक विदेशी इशाक डार भी मौजूद थे।

राष्ट्र के प्रतिनिधियों से बात करते हुए राष्ट्रपति एक निपटने और अस्वीकार करना है कि इसकी भाषा पर उसे अपत्ति है। संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक विदेशी इशाक डार भी मौजूद थे।

राष्ट्र के प्रतिनिधियों से बात करते हुए राष्ट्रपति एक निपटने और अस्वीकार करना है कि इसकी भाषा पर उसे अपत्ति है। संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक विदेशी इशाक डार भी मौजूद थे।

राष्ट्र के प्रतिनिधियों से बात करते हुए राष्ट्रपति एक निपटने और अस्वीकार करना है कि इसकी भाषा पर उसे अपत्ति है। संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक विदेशी इशाक डार भी मौजूद थे।

राष्ट्र के प्रतिनिधियों से बात करते हुए राष्ट्रपति एक निपटने और अस्वीकार करना है कि इसकी भाषा पर उसे अपत्ति है। संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक विदेशी इशाक डार भी मौजूद थे।

राष्ट्र के प्रतिनिधियों से बात करते हुए राष्ट्रपति











